

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.2866
मंगलवार, 18 मार्च, 2025/27 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी समितियां और सहकारी बैंक

2866. श्री राजीव रायः

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;
- (ख) देश में सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों के विकास के लिए नवगठित मंत्रालय द्वारा आवंटित राशि का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;
- (ग) उन सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों का राज्यवार ब्यौरा क्या है, जिन्होंने अभी तक कम्प्यूटरीकृत खाते नहीं बनाए हैं;
- (घ) क्या देश में ऐसे सहकारी बैंक हैं जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के संरक्षण के बिना सीधे सहकारी समितियों द्वारा चलाए जाते हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) के अनुसार, दिनांक 01-03-2025 तक सहकारी समितियों की राज्यवार कुल संख्या **अनुलग्नक -1** में संलग्न है। राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) और शहरी सहकारी बैंकों (UCB) की राज्य-वार संख्या **अनुलग्नक -2** में संलग्न है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्राथमिक कृषि सहकारी क्रेडिट समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए सरकार द्वारा आवंटित निधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक -3** में दिया गया है और विगत तीन वर्षों के दौरान सहकारी बैंकों सहित सहकारी समितियों के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) द्वारा संवितरित वित्तीय सहायता का ब्यौरा **अनुलग्नक -4** में दिया गया है।

(ग) नाबाड़ के पर्यवेक्षण के अधीन सभी सहकारी बैंकों का डिजिटलीकरण किया गया है और यह कोर बैंकिंग सोल्यूशन (CBS) प्लेटफार्म पर कार्य कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) सहकारी बैंक स्वाभाविक रूप से सहकारी समितियाँ हैं जो संबंधित राज्य के सहकारी सोसाइटी अधिनियम या बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 (2023 में संशोधित) के तहत पंजीकृत हैं। जब सहकारी समितियां बैंकिंग का कारोबार करती हैं, तो वे आरबीआई के नियामक दायरे में आती हैं और उन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर लागू) के प्रावधानों के तहत लाइसेंस दिया जाता है।

राज्य-वार सहकारी समितियों की संख्या

क्रम सं.	राज्य	समितियों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2231
2	आंध्र प्रदेश	17884
3	अरुणाचल प्रदेश	1302
4	असम	11325
5	बिहार	26324
6	चंडीगढ़	476
7	छत्तीसगढ़	10980
8	दिल्ली	5944
9	गोवा	5499
10	गुजरात	83748
11	हरियाणा	33300
12	हिमाचल प्रदेश	5439
13	जम्मू और कश्मीर	10124
14	झारखण्ड	11683
15	कर्नाटक	45292
16	केरल	18209
17	लद्दाख	273
18	लक्ष्द्वीप	43
19	मध्य प्रदेश	53740
20	महाराष्ट्र	222864
21	मणिपुर	11458
22	मेघालय	3152
23	मिजोरम	1320
24	नागालैंड	8017
25	ओडिशा	7598
26	पुडुचेरी	461
27	पंजाब	19237
28	राजस्थान	41095
29	सिक्किम	3797
30	तमिलनाडु	22793
31	तेलंगाना	60517
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	566
33	त्रिपुरा	3213
34	उत्तर प्रदेश	44933
35	उत्तराखण्ड	5572
36	पश्चिम बंगाल	31779
	कुल	832188

स्रोत: दिनांक 01-03-2025 के NCD पोर्टल के अनुसार

राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) और शहरी सहकारी बैंकों (UCB) की राज्य-वार संख्या

क्रम सं.	राज्य	राज्य सहकारी बैंक	जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB)	शहरी सहकारी बैंक (UCB)
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	
2	आंध्र प्रदेश	1	13	39
3	अरुणाचल प्रदेश	1	0	
4	असम	1	0	7
5	बिहार	1	23	2
6	चंडीगढ़	1	0	2
7	छत्तीसगढ़	1	6	12
8	दिल्ली	1	0	17
9	गोवा	1	0	5
10	गुजरात	1	18	212
11	हरियाणा	1	19	7
12	हिमाचल प्रदेश	1	2	5
13	जम्मू और कश्मीर	1	3	4
14	झारखण्ड	1	1	2
15	कर्नाटक	1	20	279
16	केरल	1	0	39
17	लद्दाख	0	0	
18	लक्ष्मीप	0	0	
19	मध्य प्रदेश	1	38	38
20	महाराष्ट्र	1	31	448
21	मणिपुर	1	0	
22	मेघालय	1	0	3
23	मिजोरम	1	0	
24	नागालैंड	1	0	
25	ओडिशा	1	17	10
26	पुरुडुचेरी	1	0	1
27	पंजाब	1	20	9
28	राजस्थान	1	29	38
29	सिक्किम	1	0	1
30	तमिलनाडु	1	24	101
31	तेलंगाना	1	9	70
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1	0	
33	त्रिपुरा	1	0	
34	उत्तर प्रदेश	1	50	55
35	उत्तराखण्ड	1	10	6
36	पश्चिम बंगाल	1	5	42
कुल		32	338	1454

स्रोत: दिनांक 01-03-2025 के NCD पोर्टल के अनुसार

PACs कंप्यूटरीकरण के लिए आबंटित निधियां

(राशि करोड़ रुपये)

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आबंटित बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आबंटित बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आबंटित बजट अनुमान
महाराष्ट्र	87.95	134.58	27.81
राजस्थान	23.78	78.06	52.42
गुजरात	0	106.7	44.37
उत्तर प्रदेश	11.28	43.87	50.88
कर्नाटक	40.25	61.58	21.17
मध्य प्रदेश	33.23	50.85	0
तमिलनाडु	33.2	49.84	24.95
बिहार	32.95	50.41	29.32
पश्चिम बंगाल	30.54	46.73	40.49
पंजाब	25.52	39.05	13.32
आंध्र प्रदेश	14.93	22.84	18.12
छत्तीसगढ़	14.86	22.75	20.41
हिमाचल प्रदेश	9.56	14.64	6.18
झारखण्ड	10.99	16.83	15.1
हरियाणा	4.85	8.33	3
उत्तराखण्ड	0	0	7.03
असम	6.41	9.81	6.6
जम्मू और कश्मीर	5.25	8.03	3.71
त्रिपुरा	2.95	4.5	3.03
मणिपुर	2.55	3.9	3.86
नागालैंड	0.36	0.56	3.2
मेघालय	1.23	1.13	1.97
सिक्किम	1.18	1.8	0.79
गोवा	0.32	0.5	0.44
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	1.33	0.84
पुडुचेरी	0.44	0.67	0.29
मिजोरम	0.27	0.43	0.44
अरुणाचल प्रदेश	0.15	0.24	0.09
लद्दाख	0	0.31	0.04
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0.12

सहकारी समितियों और बैंकों को NCDC द्वारा निधियों का संवितरण

(राशि करोड़ रुपये)

क्रम सं.	राज्य का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25*
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	1.69	0.56
2	आंध्र प्रदेश	9734.7	13,280.13	14732.69
3	अरुणाचल प्रदेश	0.38	-	0.16
4	असम	17.48	0.89	1.86
5	बिहार	4053.75	815.83	6.31
6	चंडीगढ़	0.03	-	0.00
7	छत्तीसगढ़	8502.24	18,991.35	28081.03
8	दमन और दीव	0	0.11	0.03
9	गोवा	0	-	0.03
10	गुजरात	370.8	586.99	297.89
11	हरियाणा	6655.24	9,887.36	12380.50
12	हिमाचल प्रदेश	12.91	1.85	4.12
13	जम्मू और कश्मीर	0.58	0.71	0.80
14	झारखण्ड	4.63	2.54	28.34
15	कर्नाटक	112.54	261.35	432.13
16	केरल	704.74	275.89	736.78
17	लक्ष्मीप			0.06
18	मध्य प्रदेश	284.4	322.86	290.07
19	महाराष्ट्र	751.16	2,101.42	3278.36
20	मणिपुर	30.38	6.60	0.39
21	मेघालय	0.14	0.22	0.12
22	मिजोरम	4.23	3.24	1.16
23	नागालैंड	1.2	0.67	0.52
24	ओडिशा	1.61	3.24	3.47
25	पंजाब	0.42	1,650.44	2000.22
26	पुडुचेरी	0.06	-	0.11
27	राजस्थान	4.91	66.09	67.33
28	सिक्किम	0.14	0.22	0.05
29	तमिलनाडु	30.49	4.28	19.29
30	तेलंगाना	9304.97	12,174.11	20982.36
31	त्रिपुरा	12.35	1.55	1.27
32	उत्तर प्रदेश	350.24	13.04	207.58
33	उत्तराखण्ड	10.5	149.13	4.56
34	पश्चिम बंगाल	63.36	4.96	2.94
35	दिल्ली + अन्य**	10.82	9.71	1016.55
	कुल	41,031.40	60,618.47	84579.64

*बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के अधीन पंजीकृत सहकारी परिसंघों तथा अन्य को शामिल करते हुए 28.01.2025** तक का वित्तीय वर्ष 2024-25 का डेटा ।
